



Research Article

ग्रामीण समाज की स्वच्छता में शौचालय निर्माण योजना की भूमिका: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

जितेन्द्र कुमार शर्मा ^{1*}, डॉ. सत्येन्द्र कुमार सिंह ²

¹ शोधार्थी, विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग, बी.एन. मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार भारत

² शोध पर्यवेक्षक, एस.एन.एस.आर. के. एस. कालेज सहरसा, बी.एन. मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत

Corresponding Author: * जितेन्द्र कुमार शर्मा

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.23262367>

सारांश

स्वच्छता मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, जिसका संबंध स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा, पर्यावरणीय सुरक्षा तथा जीवन-स्तर से है। ग्रामीण समाज में स्वच्छता की स्थिति केवल व्यक्तिगत व्यवहार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सामाजिक मान्यताओं, आर्थिक परिस्थितियों, शिक्षा, आधारभूत सुविधाओं तथा सामुदायिक सहभागिता से भी प्रभावित होती है। भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत मिशन का प्रमुख उद्देश्य स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार करना तथा खुले में शौच की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए जनभागीदारी और व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करना था। मिशन के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण को बढ़ावा दिया गया। प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज की स्वच्छता में शौचालय निर्माण योजना की भूमिका का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है तथा इसमें सरकारी रिपोर्टों, स्वच्छ भारत मिशन के आधिकारिक दस्तावेजों, जनगणना संबंधी सामग्री, शोध-पत्रों और उपलब्ध अकादमिक साहित्य को द्वितीयक स्रोतों के रूप में उपयोग किया गया है। अध्ययन में शौचालय की उपलब्धता, उपयोग, स्वच्छता संबंधी व्यवहार, महिलाओं की गरिमा एवं सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा ग्रामीण जीवन-स्तर जैसे पहलुओं पर विचार किया गया है। अध्ययन का केंद्रीय तर्क है कि शौचालय निर्माण स्वच्छता सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके स्थायी परिणाम नियमित उपयोग, पर्याप्त जल, रखरखाव, सुरक्षित अपशिष्ट प्रबंधन तथा सामाजिक जागरूकता पर निर्भर करते हैं। अतः ग्रामीण स्वच्छता को एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझना आवश्यक है।

Manuscript Information

- ISSN No: 2583-7397
- Received: 01-05-2026
- Accepted: 26-06-2026
- Published: 30-06-2026
- IJCRM:5(3); 2026: 1180-1184
- ©2026, All Rights Reserved
- Plagiarism Checked: Yes
- Peer Review Process: Yes

How to Cite this Article

शर्मा जि कु, सिंह स कु. स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के वैज्ञानिक स्वभाव का तुलनात्मक अध्ययन. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(3):1180-1184.

Access this Article Online



www.multiarticlesjournal.com

मूल शब्द: ग्रामीण समाज, स्वच्छता, शौचालय योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सामाजिक परिवर्तन, ग्रामीण विकास।

1. प्रस्तावना

स्वच्छता किसी भी समाज के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण संकेतक है। स्वच्छ वातावरण व्यक्ति के स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक प्रतिष्ठा और सामुदायिक कल्याण से संबंधित होता है। ग्रामीण समाज में स्वच्छता का प्रश्न विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वहाँ आवासीय परिस्थितियाँ, जल की उपलब्धता, आर्थिक संसाधन, सामाजिक परंपराएँ और सार्वजनिक सुविधाएँ दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं।

परंपरागत रूप से अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की प्रथा प्रचलित रही है। इसके पीछे केवल शौचालय की अनुपलब्धता ही नहीं, बल्कि सामाजिक आदतें, जागरूकता का अभाव, आर्थिक कठिनाइयाँ, जल संकट और सुविधाओं के रखरखाव से संबंधित समस्याएँ भी रही हैं। खुले में शौच से मानव मल के असुरक्षित संपर्क, पर्यावरणीय प्रदूषण और संक्रमण के जोखिम बढ़ सकते हैं। साथ ही, महिलाओं एवं किशोरियों को निजता, सुविधा और सुरक्षा से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया। ग्रामीण क्षेत्रों में इस मिशन का उद्देश्य घरेलू शौचालयों के निर्माण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता, खुले में शौच की प्रवृत्ति में कमी तथा सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना रहा है। आधिकारिक विवरण के अनुसार, वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में दस करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण की सूचना दी गई तथा छह लाख से अधिक गाँवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। यह उपलब्धि स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े स्तर पर किए गए प्रयासों को दर्शाती है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से शौचालय निर्माण योजना का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह योजना केवल भौतिक संरचना के निर्माण तक सीमित नहीं है। इसका संबंध सामाजिक व्यवहार, लैंगिक संबंधों, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और ग्रामीण समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया से भी है।

2. अध्ययन की समस्या

ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के विस्तार के बावजूद स्वच्छता से संबंधित अनेक प्रश्न बने हुए हैं। इनमें शौचालय का नियमित उपयोग, पर्याप्त जल की उपलब्धता, शौचालय की कार्यशीलता, साफ-सफाई, सुरक्षित अपशिष्ट प्रबंधन तथा व्यवहार परिवर्तन की स्थिरता प्रमुख हैं। किसी परिवार के पास शौचालय होना और उसका नियमित उपयोग करना दो अलग-अलग स्थितियाँ हैं। यदि शौचालय में जल की सुविधा नहीं है, उसकी संरचना अनुपयोगी है अथवा परिवार के सदस्य पुराने व्यवहार को अपनाते रहते हैं, तो निर्माण का अपेक्षित सामाजिक लाभ सीमित हो सकता है। इसलिए अध्ययन की प्रमुख समस्या यह समझना है कि शौचालय निर्माण योजना ग्रामीण समाज की स्वच्छता व्यवस्था में किस प्रकार योगदान देती है तथा इसके सामाजिक प्रभावों को स्थायी बनाने के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध इसी समस्या का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करता है।

3. अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. ग्रामीण समाज की स्वच्छता में शौचालय निर्माण योजना की भूमिका का अध्ययन करना।
2. शौचालय की उपलब्धता और उसके नियमित उपयोग के बीच संबंध को समझना।
3. ग्रामीण परिवारों में स्वच्छता संबंधी जागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन का विश्लेषण करना।
4. शौचालय निर्माण योजना के संदर्भ में महिलाओं की गरिमा, निजता और सुरक्षा के महत्व का अध्ययन करना।
5. स्वच्छता सुविधाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा ग्रामीण पर्यावरण के बीच संबंध का विश्लेषण करना।
6. शौचालय निर्माण योजना के क्रियान्वयन में आने वाली सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक चुनौतियों की पहचान करना।
7. ग्रामीण स्वच्छता को अधिक प्रभावी एवं टिकाऊ बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

4. अध्ययन का महत्व

इस अध्ययन का महत्व ग्रामीण स्वच्छता को एक व्यापक सामाजिक समस्या के रूप में समझने में निहित है। सामान्यतः स्वच्छता कार्यक्रमों का मूल्यांकन निर्मित शौचालयों की संख्या अथवा योजना के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं के आधार पर किया जाता है। लेकिन समाजशास्त्रीय अध्ययन इस बात पर भी ध्यान देता है कि इन सुविधाओं का उपयोग कौन करता है, उपयोग में क्या बाधाएँ हैं और उनसे ग्रामीण परिवारों के व्यवहार एवं जीवन-स्तर में किस प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। यह अध्ययन ग्रामीण समाज में स्वच्छता संबंधी मान्यताओं, पारिवारिक जिम्मेदारियों, लैंगिक असमानताओं, सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता की भूमिका को समझने में उपयोगी है। इसके निष्कर्ष ग्रामीण विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, पंचायत स्तर पर योजना निर्माण तथा स्वच्छता संबंधी जनजागरूकता कार्यक्रमों के विकास में सहायक हो सकते हैं।

5. अध्ययन क्षेत्र

समस्तीपुर जिला बिहार के मिथिला क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जिला है। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, साहित्य, कला एवं कृषि-आधारित जीवन-व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। मिथिला चित्रकला, मखाना तथा "पान, माछ, मखान मिथिला के पहचान" जैसी लोक अभिव्यक्तियाँ इसकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती हैं। समस्तीपुर जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,904 वर्ग किलोमीटर है। प्रशासनिक दृष्टि से जिले में चार अनुमंडल एवं 20 प्रखंड हैं।

प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र रोसड़ा अनुमंडल के अंतर्गत रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर ग्राम पंचायत है। रोसड़ा अनुमंडल में सिंधिया, बिथान, हसनपुर, विभूतिपुर, शिवाजीनगर एवं रोसड़ा सहित छह प्रखंड हैं। रोसड़ा प्रखंड में नगर परिषद रोसड़ा के साथ विभिन्न ग्राम पंचायतें ग्रामीण प्रशासन एवं विकास की महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं। इन्हीं में मोतीपुर ग्राम पंचायत को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है।

मोतीपुर ग्राम पंचायत मुख्यतः ग्रामीण सामाजिक एवं कृषि-आधारित परिवेश वाला क्षेत्र है। यहाँ पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, आवास, सड़क, सामाजिक सुरक्षा तथा विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता

है। प्रस्तुत अध्ययन में मोतीपुर पंचायत की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण समुदाय पर उनके प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है।

6. शोध-पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसमें मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों तथा प्रकाशित साहित्य का उपयोग किया गया है। अध्ययन के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से संबंधित सरकारी दस्तावेजों, जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्टों, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जनगणना संबंधी सामग्री, स्वच्छता विषयक शोध-पत्रों तथा ग्रामीण विकास से संबंधित अकादमिक साहित्य को प्रासंगिक स्रोतों के रूप में लिया गया है।

अध्ययन में विषयवस्तु विश्लेषण की पद्धति अपनाई गई है। इसके अंतर्गत शौचालय निर्माण, नियमित उपयोग, स्वच्छता संबंधी व्यवहार, महिलाओं की गरिमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्वच्छता तथा सामुदायिक सहभागिता से संबंधित पहलुओं का विश्लेषण किया गया है।

यह अध्ययन उपलब्ध प्रकाशित सूचनाओं पर आधारित है। इसमें प्राथमिक सर्वेक्षण अथवा साक्षात्कार से प्राप्त नए आँकड़ों का दावा नहीं किया गया है। किसी विशिष्ट गाँव, पंचायत या प्रखंड की उपलब्धि का निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए संबंधित क्षेत्र के सत्यापित सरकारी आँकड़ों की आवश्यकता होगी।

7. स्वच्छ भारत मिशन एवं शौचालय निर्माण योजना

स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। इसका उद्देश्य स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़ना, घरेलू शौचालयों के निर्माण को प्रोत्साहित करना तथा खुले में शौच की प्रवृत्ति को समाप्त करने की दिशा में कार्य करना था। ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन के माध्यम से व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के साथ-साथ स्वच्छता संबंधी जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन पर भी बल दिया गया। बाद के चरण में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा खुले में शौच से मुक्त स्थिति को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

शौचालय निर्माण योजना का प्रमुख सामाजिक महत्व यह है कि इससे ग्रामीण परिवारों को घर के निकट स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराने का अवसर मिलता है। घरेलू शौचालय परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने, निजता बनाए रखने तथा खुले में शौच पर निर्भरता कम करने में सहायक हो सकता है। किसी भी योजना की सफलता केवल उसके निर्माण संबंधी लक्ष्यों से निर्धारित नहीं होती। उसके उपयोग, रखरखाव, गुणवत्ता तथा सामाजिक स्वीकार्यता का मूल्यांकन भी आवश्यक है। इसलिए शौचालय निर्माण योजना को ग्रामीण स्वच्छता के व्यापक कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में समझना चाहिए।

8. ग्रामीण स्वच्छता में शौचालय निर्माण की भूमिका

शौचालय निर्माण ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता की एक आवश्यक सुविधा प्रदान करता है। इससे मानव मल के असुरक्षित संपर्क को कम करने और आसपास के वातावरण को दूषित होने से बचाने में सहायता मिल सकती है। घरेलू शौचालय की उपलब्धता परिवार के दैनिक

जीवन को सुविधाजनक बनाती है तथा शौच के लिए दूरस्थ स्थानों पर जाने की आवश्यकता को कम कर सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति घर के भीतर की सुविधाओं के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों, गलियों, नालियों, जलस्रोतों और अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था पर भी निर्भर करती है। इसलिए शौचालय निर्माण को गाँव की समग्र स्वच्छता व्यवस्था से जोड़कर देखना आवश्यक है। यदि शौचालय का उपयोग नियमित रूप से किया जाता है और मानव मल का सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित होता है, तो स्वच्छता व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सकती है। इसके विपरीत, अनुपयोगी शौचालय, अपर्याप्त जल, खराब रखरखाव अथवा असुरक्षित अपशिष्ट निस्तारण से अपेक्षित लाभ सीमित हो सकते हैं।

अतः शौचालय निर्माण योजना ग्रामीण स्वच्छता के लिए आधारभूत भूमिका निभाती है, लेकिन इसके साथ जल, सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन और व्यवहार परिवर्तन के उपायों का समन्वय आवश्यक है।

9. स्वच्छता संबंधी व्यवहार परिवर्तन

समाजशास्त्र के अनुसार मानव व्यवहार सामाजिक परिस्थितियों, परंपराओं, पारिवारिक आदतों, शिक्षा और सामुदायिक मान्यताओं से प्रभावित होता है। इस दृष्टि से स्वच्छता संबंधी व्यवहार को केवल व्यक्तिगत निर्णय के रूप में नहीं देखा जा सकता।

यदि किसी ग्रामीण समुदाय में लंबे समय से खुले में शौच की परंपरा रही है, तो केवल शौचालय उपलब्ध कराने से व्यवहार में तत्काल और स्थायी परिवर्तन सुनिश्चित नहीं होता। इसके लिए स्वच्छता के महत्व की जानकारी, सामाजिक संवाद, सामुदायिक सहभागिता तथा उपयोग योग्य सुविधाओं की उपलब्धता आवश्यक है।

विद्यालय, पंचायत, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वयं सहायता समूह, स्वास्थ्यकर्मी और स्थानीय नेतृत्व स्वच्छता संबंधी जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जब समुदाय स्वच्छता को व्यक्तिगत सुविधा के साथ सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करता है, तब व्यवहार परिवर्तन के स्थायी होने की संभावना बढ़ती है।

इस प्रकार, शौचालय निर्माण योजना की प्रभावशीलता का आकलन करते समय सामाजिक जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन को भी प्रमुख स्थान देना चाहिए।

10. महिलाओं की गरिमा, निजता एवं सुरक्षा

शौचालय निर्माण योजना का एक महत्वपूर्ण सामाजिक पक्ष महिलाओं और किशोरियों की गरिमा, निजता तथा सुविधा से जुड़ा है। जिन परिवारों में घरेलू शौचालय उपलब्ध नहीं होता, वहाँ महिलाओं को कई बार शौच के लिए घर से बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती है। इससे समय, सुविधा, निजता तथा सुरक्षा से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

घर में सुरक्षित एवं उपयोग योग्य शौचालय उपलब्ध होने से महिलाओं की दैनिक कठिनाइयाँ कम हो सकती हैं। विशेषकर रात्रि, खराब मौसम, बीमारी तथा गर्भावस्था जैसी परिस्थितियों में घरेलू शौचालय उपयोगी हो सकता है।

शौचालय की उपलब्धता के साथ पर्याप्त जल, स्वच्छता, प्रकाश, सुरक्षित संरचना और नियमित रखरखाव भी आवश्यक हैं। महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना निर्मित सुविधाएँ अपेक्षित लाभ प्रदान नहीं कर सकतीं। इसलिए ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों के

मूल्यांकन में महिलाओं के अनुभवों, आवश्यकताओं और सुविधा को विशेष महत्व देना चाहिए। इससे स्वच्छता को केवल भौतिक निर्माण नहीं, बल्कि गरिमा और सामाजिक समानता से जुड़े विषय के रूप में समझा जा सकेगा।

11. सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय स्वच्छता

स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच घनिष्ठ संबंध है। खुले में शौच तथा मानव मल का असुरक्षित निस्तारण जल, मिट्टी और आसपास के वातावरण को दूषित कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में रोगजनक जीवों के संपर्क और संक्रमण का जोखिम बढ़ सकता है। घरेलू शौचालय का सुरक्षित उपयोग, हाथ धोने की आदत, स्वच्छ पेयजल तथा अपशिष्ट का उचित प्रबंधन मिलकर स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में योगदान दे सकते हैं। बच्चों, बुजुर्गों तथा अन्य संवेदनशील समूहों के लिए स्वच्छ वातावरण विशेष महत्व रखता है। फिर भी, किसी क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तन केवल शौचालय निर्माण पर निर्भर नहीं करता। जल की गुणवत्ता, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएँ, आवासीय परिस्थितियाँ और व्यक्तिगत स्वच्छता भी महत्वपूर्ण कारक हैं। इसलिए शौचालय निर्माण के कारण रोगों में निश्चित कमी का दावा करने के लिए विश्वसनीय स्वास्थ्य आँकड़ों और तुलनात्मक अध्ययनों की आवश्यकता होती है।

ग्रामीण स्वच्छता का व्यापक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि घरेलू शौचालयों के साथ गाँव में नालियों, जलस्रोतों, कचरा संग्रहण और अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था भी विकसित की जाए।

शौचालय निर्माण योजना ग्रामीण परिवारों के जीवन-स्तर में सुधार की संभावनाओं से जुड़ी है। घर में शौचालय होने से दैनिक जीवन अधिक सुविधाजनक हो सकता है और परिवार के सदस्यों को स्वच्छता की निजी सुविधा मिल सकती है। यह ग्रामीण आवास की आधारभूत सुविधाओं में सुधार का महत्वपूर्ण पहलू है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक परिवर्तन तब दिखाई देता है, जब किसी समुदाय की जीवन-शैली, मान्यताओं और दैनिक व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। स्वच्छता संबंधी जागरूकता, शौचालय के नियमित उपयोग और सामुदायिक सफाई में सहभागिता से ग्रामीण समाज में स्वच्छता के नए सामाजिक मानदंड विकसित हो सकते हैं। सभी ग्रामीण परिवारों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ समान नहीं होती हैं। कुछ परिवारों को स्थान की कमी, जल संकट, निर्माण की गुणवत्ता, मरम्मत की लागत अथवा अन्य आधारभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ग्रामीण जीवन-स्तर में सुधार का आकलन करते समय परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और स्थानीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

13. योजना के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ

शौचालय निर्माण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और स्थायी उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित चुनौतियाँ महत्वपूर्ण हैं-

पहली चुनौती: नियमित उपयोग। शौचालय का निर्माण होने के बाद भी उसके नियमित उपयोग को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

दूसरी चुनौती: जल की उपलब्धता। पर्याप्त जल के अभाव में शौचालय का उपयोग और साफ-सफाई कठिन हो सकती है।

तीसरी चुनौती: गुणवत्ता एवं रखरखाव। कमजोर निर्माण, मरम्मत की समस्या और सफाई की कमी से शौचालय अनुपयोगी हो सकता है।

चैथी चुनौती: सामाजिक मान्यताएँ। लंबे समय से प्रचलित आदतों तथा व्यवहार में परिवर्तन के लिए निरंतर जागरूकता आवश्यक है।

पाँचवीं चुनौती: अपशिष्ट प्रबंधन। शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण स्वच्छता व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

छठी चुनौती: सामाजिक एवं आर्थिक असमानता। संसाधनों की कमी तथा अलग-अलग पारिवारिक परिस्थितियाँ स्वच्छता सुविधाओं के उपयोग को प्रभावित कर सकती हैं।

इन चुनौतियों के समाधान के लिए सरकारी प्रयासों के साथ स्थानीय संस्थाओं, पंचायतों और ग्रामीण समुदाय की सहभागिता आवश्यक है।

14. निष्कर्ष

शौचालय निर्माण ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता की बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है। शौचालय की उपलब्धता और उसके नियमित उपयोग को अलग-अलग संकेतकों के रूप में समझना आवश्यक है। स्वच्छता संबंधी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन के लिए शिक्षा, जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता महत्वपूर्ण हैं। घरेलू शौचालय महिलाओं की निजता, सुविधा और गरिमा में सुधार की संभावना प्रदान करता है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए सुरक्षित अपशिष्ट प्रबंधन, जल की उपलब्धता तथा व्यक्तिगत स्वच्छता आवश्यक हैं। ग्रामीण स्वच्छता के स्थायी परिणामों के लिए केवल निर्माण पर नहीं, बल्कि उपयोग, रखरखाव और निगरानी पर भी ध्यान देना चाहिए।

15. सुझाव

ग्रामीण समाज में स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं-

1. प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित, स्वच्छ और उपयोग योग्य शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएँ।
2. शौचालय निर्माण के साथ उसके नियमित उपयोग और रखरखाव के महत्व पर बल दिया जाए।
3. पंचायत स्तर पर शौचालय की उपलब्धता, कार्यशीलता तथा स्वच्छता सुविधाओं से संबंधित सत्यापित आँकड़े संकलित किए जाएँ।
4. विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
5. महिलाओं, किशोरियों, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाओं का विकास किया जाए।
6. शौचालयों की मरम्मत, जल की उपलब्धता और सुरक्षित अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए।
7. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को गाँव की समग्र स्वच्छता योजना से जोड़ा जाए।
8. पंचायत और समुदाय की सहभागिता से स्वच्छता कार्यक्रमों की नियमित निगरानी की जाए।
9. स्थानीय सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर स्वच्छता संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए।

10. भविष्य के शोध में शौचालय निर्माण, नियमित उपयोग, व्यवहार परिवर्तन और स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए।

संदर्भ सूची

1. दुबे एससी. भारतीय ग्राम. नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट; 2004.
2. श्रीनिवास एमएन. आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन. नई दिल्ली: मैकमिलन पब्लिशर्स; 2009.
3. योगेंद्र सिंह. भारत में सामाजिक परिवर्तन: एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण. नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन्स; 2006.
4. घुर्ये जीएस. भारतीय ग्रामीण समाज. नई दिल्ली: पॉपुलर प्रकाशन; 2011.
5. मजूमदार डीएन, मदान टीएन. भारतीय सामाजिक मानवशास्त्र. नई दिल्ली: मैकमिलन पब्लिशर्स; 2010.
6. देसाई एआर. भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र. मुंबई: पॉपुलर प्रकाशन; 2005.
7. सिंह योगेंद्र. भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन. जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स; 2012.
8. भारत सरकार. भारत की जनगणना 2011: जिला जनगणना पुस्तिका, समस्तीपुर. नई दिल्ली: भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय; 2011.
9. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): वार्षिक रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2019.
10. भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): आधिकारिक विवरण एवं दिशा-निर्देश. नई दिल्ली: भारत सरकार.
11. भारत सरकार. जनगणना 2011: आवास एवं घरेलू सुविधाओं से संबंधित आँकड़े. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2011.
12. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), 2019-21. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2021.
13. भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय. राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (NARSS), 2019-20. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2020.
14. भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय. स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022: रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2022.
15. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण). नई दिल्ली: भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग. उपलब्ध: [स्वच्छ भारत मिशन \(ग्रामीण\)](#)
16. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) डैशबोर्ड. नई दिल्ली: भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय. उपलब्ध: [स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण डैशबोर्ड](#)

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Corresponding Author



जितेन्द्र कुमार शर्मा समाजशास्त्र विषय के शोधार्थी हैं। वे विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग, बी.एन. मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत से संबद्ध हैं। उनका अकादमिक रुचि-क्षेत्र समाजशास्त्रीय अध्ययन, सामाजिक परिवर्तन, ग्रामीण समाज तथा समकालीन सामाजिक समस्याओं के अध्ययन और विश्लेषण से संबंधित है। वे शोध एवं अकादमिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।